entire House is to grant interim relief to the Central Government employees I only wanted to voice that feeling.

SOME HON. MEMBERS : *rose*—

MR. DEPUTY-SPEAKER : I would request hon. Members to kindly co-operate. Let us move on to the regular business before us...

SHRI S. KANDAPPAN : *rose*—

MR. DEPUTY-SPEAKER : I shall allow Shri S. Kandappan later.

SHRI JYOTIRMOY BASU : I want to make a submission on a different issue...

MR. DEPUTY-SPEAKER : Not now. Let us finish the business before us and then we shall come to that.

श्री मधु लिमये (मुंगेर) : श्री इंद्र जी गुजराल ने वादा किया था कि वह सदन में उपस्थित रहेंगे। लेकिन पता नहीं वह कहां गायब हो गये हैं । वह इसके बारे में बयान देने वाले थे । समाचार भारती एजंसी का मामला मैं उठा रहा हूं। इस सदन में उन्होंने भ्राश्वासन दिया था कि इस एजंसी के बारे में ट्रस्ट बनाने की योजना वह सदन के सामने रखने जा रहे हैं। भ्रभी तक इस योजना की रूपरेखा सदन के सामने नहीं भ्राई है। यह सुनने में भ्रा रहा है कि जो वर्तमान डायरेक्टर हैं उन्हीं को ही भ्राजीवन ट्रस्टी बनाने ये जा रहे हैं। उसमें एक दो सरकार के चमचे जोड़ दिये जायेंगे । लेकिन इससे मामला ठीक होने वाला नहीं है। सबसे पहले मैं निवेदन करूगा कि जिन डायरेक्टर्ज ने इस एजंसी को चौपट किया है कम्पनी कानून की दो धाराम्रों को हिसाब-किताब के बारे में तोड़ा है 210 भ्रौर 220, उनको इस बोर्ड भ्राफ ट्रस्टीज में बिल्कुल नहीं रखा जाना चाहिये ।

दूसरी बात यह है कि भ्राजीवन ट्रस्टीशिप का कोई सवाल नहीं होना चाहिये । हर तीन साल के बाद एक तिहाई ट्रस्टीज को बदला जाये भ्रौर कम से कम बोर्ड भ्राफ ट्रस्टीज में एक तिहाई समाचार एजंसी में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं और वकिंग जरनलिस्ट हैं, उनके प्रतिनिधि होने चाहिए । भ्राज बैनेट कोलमैन का मामला यहां आया था। उसके बारे में सरकार ने जो भ्राश्वासन दिया था, उसको पूरा नहीं किया गया । कम से कम समाचार भारती से यह काम प्रारम्भ किया जाये । सरकार कम्पनी कानून के उल्लंघन के बारे में गम्भीरता से सोचे। लेबर कोर्ट में कई कर्मचारियों भ्रौर जर्नलिस्ट्स के केसिज पड़े हुए हैं । एजेन्सी के प्रतिनिधि जान-बूझ कर कोर्ट में नहीं जाते हैं । उनको दस रुपये जुर्माना भी हुआ है, लेकिन उन पर कोई असर नहीं हो रहा है ।

इस कम्पनी की कई शाखाओं में कर्मचारियों भ्रौर जर्नलिस्ट्स को पिछले महीने उनके वेतन का भुगतान नहीं हुम्रा है । पटना की शाखा में सात हजार रुपये की चोरी भी हुई है। जब कर्मचारियों और जर्नलिस्ट्स के द्वारा शिकायत की जाती है, तो एजेन्सी के कार्यालय में फर्जी पत्र तैयार किये जाते हैं उन पर जबर्दस्ती हस्ताक्षर लिए जाते हैं भ्रौर कहा जाता है कि एजेन्सी के बारे में कोई शिकायत नहीं है । इस तरह का एक फर्जी पत्र मैं भ्राप की इजाजत से सदन-पटल पर रखना चाहता हूं। इसमें "जैन" लिखा हुम्रा है । यह कौन है ? समाचार भारती के मुख्य कार्यालय में जो स्टेनोग्राफी का काम करता है, उससे पत्र तैयार करवा कर भोपाल की शाखा की भ्रोर से पेश किये जाते हैं । समझ में नहीं आता है कि यह सारा नाटक क्या है।

इसके अतिरिक्त इस एजेन्सी के कर्मचारियों के विक्टिमाइजेशन का मामला है, वेज बोर्ड भ्रौर वेज कमेटी की सिफारिशों को कार्यान्वित करने का मामला है, 4 प्रतिशत बोनस देने का मामला है भ्रौर डी० ए० को महंगाई के

[श्री मधु लिमये]

साथ जोड़ने का भी मामला है । इन सब मामलों के बारे में मैं श्री गुजराल से खुलासा चाहता हूं ।

अन्त में मैं जो बात कहना चाहता हूँ, वह औद्योगिक विकास मंत्रालय के बारे में है । विदेशी कोलैबोरेशन के बारे में इस सरकार ने यह नीति घोषित की है, और इस सदन की भी यह राय है, कि जिन मामलों के बारे में हमारे देश में टेकनिकल नो-हाऊ है, उनमें विदेशी कोलैबोरेशन नहीं लेना चाहिये । लेकिन मुझे पता चला है कि बियर बनाने के लिये नयी ब्रियुरीज खोली जा रही हैं और बिलायत की ब्रियुरीज या कम्पनीज के साथ कोलैबोरेशन होगा । यह बहुत ही अफसोस की बात है । वित्त मंत्री बैठे हुए हैं । क्या इस तरह के कोलैबोरेशन एग्रीमेंट में विदेशी मुद्रा का अपव्यय नहीं होगा, विदेशी मुद्रा बर्बाद नहीं होगी ?

कल प्रधान मंत्री जी ने स्वयं कहा कि हम विज्ञान को विकसित करने का प्रयास करेंगे । एक ओर सरकार वैज्ञानिकों और टेकनीशन्ज को प्रोत्साहन देना चाहती है और दूसरी ओर बिस्किट बनाने के लिये आइसक्रीम बनाने के लिए, कोका कोला के लिये ...(व्यवधान)...और ब्रेसियर्स के लिये—एक दफा मैंने इसका उल्लेख किया था ; अब मैं बार-बार नहीं करना चाहता हूं—विदेशी कोलैबोरेशन प्राप्त करने की बात की जाती है । क्या सरकार की कोई आर्थिक नीति है या नहीं और क्या औद्योगिक विकास मन्त्रालय सरकार की वित्तीय और आर्थिक नीति के तहत चलेगा या उसके खिलाफ चलेगा ? एक ओर विज्ञान की गरिमा और वैज्ञानिकों को प्रोत्साहन देने की बात की जाती है और दूसरी ओर हिन्दुस्तान में जो टेकनिकल नो-हाऊ और विज्ञान है, उसको खत्म करने की बात की जा रही है । मैं इस के बारे में सरकार से खुलासा चाहता हूँ ।

SHRI S. KANDAPPAN (Mettur) : I sought your permission to raise the question about the strike in the Indian Overseas Bank by the employees. Before I go to that subject, kindly permit me to say a few words about the atrocities perpetrated against the Harijans.

I am not going to sermonise on that just now. I only request the House through you to bear it in mind that this is not the first time this is happening. Even earlier, when we wanted to discuss something about social welfare, it was always put at the fag end of a session and the discussion was adjourned or the House adjourned without starting a discussion.

What I would like to insist upon its that this is a very serious matter. If we are going to treat it in the casual manner in which the Government is treating it, then I am afraid a bloody revolution will start in the country. They cannot bear this any more. That is the situation which they have reached. So, I would beg of the House through you to see that we start this discussion today, right now, and if possible to go ahead with it even sitting late in the night. Or, as somebody suggested, if need be, let us extend the sitting up to tomorrow and conclude the discussion on the subject. I feel very seriously about it.

Now, coming to my subject, I was referring to the strike. I am sorry that the Minister of State, Shri Sethi, who was here a little while ago, is not here now. This strike is very unfortunate, because it comes in the wake of so many other strikes that are taking place in our country. It is not only causing a lot of inconvenience to the clients and the consumers but it is a proof of mismanagement in the nationalised banks.

I shall just briefly put the case before the House. About two weeks back, there was some kind of struggle and a sort of difference of opinion between the employees of the Overseas Bank and the authorities, in the Defence Colony branch. The Secretary of the Union concerned with this problem went there and sorted out the difference, and he was able to amicably settle it. But what